



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशन
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1994/आश्विन : 7, 1916

No. 497]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1994/ASVINA 7, 1916

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(निवेश प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार
(ईसीआईआईपी) योजना 1993

का.आ. 719 (अ) : —केन्द्रीय सरकार एतद्-
द्वारा भारत में संयुक्त उद्यम की स्थापना के लाभ के लिए
यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा निवेशों को तरल बनाने के
लिए निम्नलिखित योजना को अधिसूचित करता है :—

- (1) इस योजना का नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार (ई सी आई आई
पी) योजना, 1993 होगा।
- (2) यह योजना 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी मानो
जाएगी।

2. परिभाषाएं : इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से
अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) “यूरोपीय आर्थिक समुदाय” का अभिप्राय 25
मार्च, 1957 को रोम संधि द्वारा संस्थापित
यूरोपीय आर्थिक समुदाय है।
- (ख) “संस्थागत साझेदार” का अभिप्राय केन्द्रीय सरकार
द्वारा इस संवध में स्वीकृत वित्तीय संस्था है।
- (ग) “सुविधा” का अभिप्राय यूरोपीय आर्थिक समुदाय
द्वारा इसकी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार
योजना के तहत प्रस्तावित चार में से किसी भी
एक सुविधा से है जो इस योजना के अनुबन्ध में
दी गयी है।

3. योजना की संरचना :

1. यूरोपीय आर्थिक समुदाय न एक वित्तीय दस्तावेज
तैयार किया है जिसे एशिया, लैटिन अमेरिका तथा भूमध्य-
सागरीय देशों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए
यूरोपीय समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय निवेश साझेदार (ई सी आई
आई पी) योजना कहा गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय
लक्ष्य देश में वित्तीय संस्थाओं के साथ आधारभूत कार्यों पर

हस्ताक्षर करता है और इन साझेदार वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अपनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ई सी आई आई पी का उद्देश्य विशिष्ट रूप से लघु और मध्यम आकार की कंपनियों को अपनी सहायता प्रदान करना है किन्तु बड़ी कंपनियां भी, यदि उनकी परियोजनाएं विशेष रूप से देश के विकास में रुचि वाली हों, लाभ उठा सकती हैं।

2. यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने अब तक भारत में तीन वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आई सी आई सी आई, आई डी बी आई, और भारत का निर्यात-आयात बैंक, के साथ समझौता जपान पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय भविष्य में अन्य वित्तीय संस्थाओं और/अथवा भारत में स्थित बैंकों के साथ इसी प्रकार के समझौता जानों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय कर सकता है।

3. यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यह मंशा व्यक्त की है कि वह ई सी आई आई पी योजना के तहत निवेशों से उद्भूत व्याज, लाभांशों अथवा पूंजीगत लाभों को प्रत्यावर्तित करने का इरादा नहीं रखता। समुदाय की इस अभिव्यक्त मंशा को ध्यान में रखते हुए कि वह ई सी आई आई पी योजना के तहत किए गए निवेशों से उद्भूत शेयरों की बिक्री से हुई प्राप्तियों अथवा लाभांशों को प्रत्यावर्तित करने का विचार नहीं रखता और ऐसी प्राप्तियों को भारत में पुनः निवेश करने की मंशा रखता है और जो, जहां तक भारत सरकार का संबंध है, अभी तक तरजीही प्रबन्ध ही है, भारत सरकार ने भारत में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की इस योजना के तहत अपनी निधियों को निवेश किए जाने से प्राप्त व्याज, लाभांशों अथवा पूंजीगत लाभों के जरिए प्राप्त किसी भी आय पर आयकर में छूट देने की व्यवस्था करने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 10 में नया खण्ड (23-ख ख ख) जोड़ा है। यह छूट दिनांक 1-4-1994 से प्रभावी होगी और तदनुसार मूल्यांकन वर्ष 1994-95 (आयकर वर्ष 1993-94 के लिए संगत) और परवर्ती वर्षों में लागू होगी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दिनांक 1-4-1994 को अथवा उसके बाद प्राप्त सभी ऐसी आय पर तदनुसार कर से छूट मिलेगी।

4. निवेश और विनिवेश

1. यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा ई सी आई आई पी योजना के तहत किए जाने वाले निवेशों को दिनांक 24-7-1991 की औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य के उद्देश्य के लिए विदेशी निवेश न मानकर घरेलू निवेश माना जाएगा। ई सी आई आई पी योजना के तहत किए जाने वाले निवेशों को भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उद्देश्य के लिए प्रमोटर्स के कोट ऑफ रूप में नहीं माना जाएगा। अन्य सभी अभिप्राय में भी ई सी आई आई पी योजना के तहत किए जाने वाले यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निवेशों को साझेदार संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले निवेशों के सममूल्य पर ही माना जाएगा।

2. सभी निवेश यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा “यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार” की अनुमोदित साझेदार संस्थाओं, जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ओर से निवेश यात्रों को धारण करेंगे, के माध्यम से किए जाएंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय समय-समय पर यथा संशोधित 15-9-1992 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनिवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार “यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार” की साझेदार संस्थाओं के जरिए भी विनिवेश कर पाएगा। जब भी विनिवेश किया जाएगा, वह इन साझेदार संस्थाओं द्वारा उपयुक्त वर्गों में किया जाएगा, ताकि बेची गई स्टिक की स्टॉक एक्सचेंज की कीमतों में कम से कम विघ्न अथवा अस्मव्यस्तता हो। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत सरकार को इंगित किया है कि विनिवेश से हुई आय तथा उससे वमूल की गई निधियों को इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की निवेश-योग्य निधियों के रूप में पुनः निवेशित किया जाएगा।

3. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ओर से “यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार” की साझेदार संस्थाओं द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार की निधियों में से यह इक्विटी धारिता ऐसी किसी भी इक्विटी के अलावा होगी जो इन संस्थाओं द्वारा उनकी अपनी निधियों में से अथवा यूरोपीय देशों से आने वाले किसी विदेशी निवेशकों की इक्विटी में से धारण की गई हो।

5. साझेदार संस्थाओं की पात्रता

1. भारतीय वित्तीय संस्थाएं जो “यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार” के तहत उसकी किसी सुविधा हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय की साझेदार संस्था बनने की इच्छुक हैं, ताकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋण तथा उनके द्वारा संबंधित औद्योगिक और वित्तीय उद्यमों में इक्विटी सहभागिता प्राप्त की जा सके, उन्हें इस संबंध में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

2. यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए “यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार” योजना के अन्तर्गत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा राज्य वित्त निगमों जैसी साझेदार संस्थाओं के साथ अनेकानेक “समझौता जपान” निष्पादित करना संभव होगा। भारत सरकार के साथ एक बार समझौता जपान/आधारभूत करार हो जाने तथा स्वीकृत किए जाने के बाद, इस योजना में तदनुसार उपयुक्त संशोधन घोषित किए जाएंगे।

6. यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार द्वारा प्रशान की गई निधियों का उपयोग

1. भारत में अनुसृत संयुक्त उद्यमों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार" संबंधी सुविधाओं के तहत सभी निवेश, जैसे अलग-अलग निवेशों हेतु केन्द्रीय सरकार के किसी अनुमोदन की अपेक्षा के बिना, साझेदार संस्थाओं द्वारा किए जाएंगे।

2. साझेदार संस्थाएं यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ओर से तथा उनके निवेशों की बिक्री से हुई आय, यदि कोई हो, को जमा करने के लिए, "यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार" संबंधी सुविधाओं के तहत उनके द्वारा प्रबंध की जा रही निधियों के लिए अपने बही-खातों में अलग लेखा-विवरण रखेंगे।

7. कर से छूट

1. यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कर से छूट केवल "यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार"

संबंधी निधियों से किए गए निवेशों के संबंध में मिलेगी, जो "यूरोपीय आर्थिक समुदाय के द्वारा साझेदार संस्थाओं" जरिए, भारत में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों से आने वाले यूरोपीय निवेशकों के साथ औद्योगिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए आधार-धन (ग्रीड मनी) के रूप में इस्तेमाल की जाएगी।

2. इस योजना के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय का लाभान्श, व्याज पर आयकर तथा विनिवेश पर पूंजी लाभ कर से छूट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देश से आने वाले विदेशी निवेशकों द्वारा धारित इक्विटी अथवा "यूरोपीय आर्थिक समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत साझेदार" की साझेदार संस्थाओं द्वारा उनकी अपनी निधियों में से धारित इक्विटी के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी।

[सं 15/93/89-एफ आइ एण्ड टी]

पी. जे. नायक, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

	सुविधा 1	सुविधा 2	सुविधा 3	सुविधा 4
प्रचालन का स्वरूप	संभावित संयुक्त उद्यम, परियोजनाओं तथा साझेदारों का पता लगाना।	संयुक्त उद्यम आरंभ करने से पहले के प्रचालन।	पूँजीगत अपेक्षाओं का वित्तपोषण।	मानव संसाधन विकास; प्रशिक्षण एवं प्रबंध सहायता।
लाभभोगी	वाणिज्य मण्डल, व्यावसायिक एंसेम्बल, सरकारी अधिकरण और ई.सी.आई.आई.पी. द्वितीय संस्थाएं/पृथक कम्पनियां सुविधा 1 से लाभ प्राप्त नहीं कर सकतीं।	संयुक्त उद्यम निवेश परियोजना चलाने की इच्छुक पृथक अथवा संयुक्त रूप से, स्थानीय अथवा यूरोपीय कम्पनियां।	यूरोपीय समुदाय तथा पात्र देशों के साझेदारों द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यम। दोनों साझेदारों में सार्थक हिस्सेदारी होनी चाहिए। स्थानीय कम्पनियों, जो यूरोपीय समुदाय की कम्पनी के साथ लाइसेंसिंग तथा तकनीकी सहायता करार के तहत कार्य करती हैं, में निवेश।	
सम्पर्क	लाभभोगी यूरोपीय समुदाय को सीधे अथवा वित्तीय संस्था के जरिए आवेदन कर सकता है।		आवेदन वित्तीय संस्था के जरिए किया जाए।	
वित्त का स्वरूप	अनुदान	व्याज मुक्त अग्रिम जो बाद में अनुदान, ऋण अथवा इक्विटी में परिवर्तित की जाए।	इक्विटी धारिता अथवा इक्विटी ऋण।	व्याज मुक्त ऋण।
			वित्तीय संस्था परियोजना में सह वित्त पोषण अवश्य करें।	
उपलब्ध धनराशि	अधिकतम 100,000 ई.सी.यू.	अधिकतम 250,000 ई.सी.यू.।	अधिकतम 100,000 ई.सी.यू.।	अधिकतम 250,000 ई.सी.यू.।
	प्रति परियोजना अधिकतम कुल सहायता 1,00,000 ई.सी.यू. है।			
सीमाएं	लागत के 50% तक।	लागत के 50% तक।	संयुक्त उद्यम की पूंजी का 20%।	लागत के 50% तक।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Investment Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1994.

European Economic Community International Institutional Partners (ECIIP) Scheme, 1993

S.O. 719(E).—Central Government hereby notifies the following scheme for facilitating investments by the European Economic Community for the benefit of establishment of Joint Ventures in India.

1. (i) This Scheme may be called the European Economic Community International Institutional Partners (ECIIP) Scheme 1993.

(ii) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 1993.

2. Definitions.—In this Scheme, unless the context otherwise requires :—

- (a) "European Economic Community" means the European Economic Community (EEC) established by the Treaty of Rome of 25th March, 1957.
- (b) "Institutional Partner" means a financial institution approved in this behalf by the Central Government.
- (c) "Facility" means any of the 4 facilities offered by the European Economic Community under its International Institutional Partners Scheme, as given in the Annexure to this Scheme.

3. Structure of the Scheme

(1) The European Economic Community has developed a financial instrument called the European Community International Investment Partners (ECIIP) Scheme to promote joint ventures in Asia, Latin American and the Mediterranean countries. EEC signs framework agreements with financial institutions in the target country, and makes available its financial assistance through these partner financial institutions. ECIIP specifically aims its assistance at small and medium sized companies, but larger companies can also benefit, if their projects are particularly interesting for the development of the country.

(2) EEC has so far entered into Memoranda of Understanding (MOUs) with 3 financial institutions in India Viz, ICICI, IDBI and Exim Bank of India. EEC may in future decide to have similar MOUs with other financial institutions and/or Banks in India.

(3) The European Economic Community has expressed an intention that the Community does not intend to repatriate interest, dividends, or capital gains arising out of the investments under the ECIIP Scheme. Noting the expressed intention of the Community that the Community does not intend to repatriate proceeds of sale of shares or dividends arising out of the investments made under ECIIP Scheme, and intends to re-invest such proceeds in India, which, is also the preferred arrangement in so far as the Government of India is concerned, the Government of India has inserted a new Clause (23BBB) in Section 10 of Income-Tax Act to provide income tax exemption on any income of the European Economic Community derived in India by way of interest, dividends or capital gains from investments made out of its funds under this Scheme. This exemption will take effect from 1-4-94, and will, accordingly, apply in relation to Assessment Year 1994-95 (relevant for the Income Year 1993-94) and subsequent years. All such incomes derived by European Economic Community on or after 1-4-1993 would be tax exempt accordingly.

4. Investments and disinvestments

(1) The investments made by the European Economic Community under the ECIIP Scheme would be counted as domestic investments, and not foreign investments, for the purpose of the statement of Industrial Policy dated 24-7-1991. Investments under the ECIIP Scheme would not be counted as Promoters' quota for the purpose of Securities and Exchange Board of India (SEBI) guidelines. In all other sense also, investments of the European Economic Community under the ECIIP Scheme would be treated at par with the investments of the partner institutions.

(2) All the investments would be made by EEC through ECIIP approved partner institutions who would hold the investment instruments on behalf of EEC. EEC would be able to disinvest also through the ECIIP partner institutions, in accordance with the disinvestment guidelines issued by the Reserve Bank of India on 15-9-1992, as modified from time to time. Disinvestment when made would be made in suitable lots by these partner institutions, so as to have minimum disturbance of dislocation of the stock exchange prices of the scrips unloaded. EEC has indicated to Government of India that disinvestment proceeds, and funds realised therefrom, would also be reinvested as investible funds of EEC for projects approved under this Scheme.

(3) This equity holding by ECIIP partner institutions on behalf of EEC out of ECIIP funds would be in addition to any equity which may be held by these institutions out of their own funds, or equity of any foreign investors hailing from European Countries.

5. Eligibility of partner Institutions.

(1) Indian Financial Institutions desiring to become partner institution of EEC for any of its facilities under ECIP, in order to seek loans and equity participation from EEC in Industrial and Financial ventures promoted by them would be required to be approved in this behalf by the Government of India.

(2) It would be possible for the European Economic Community to enter into any number of Memoranda of Understanding with partner institution among Banks, Financial Institutions, State Industrial Development Corporations and State Finance Corporations under the ECIP Scheme. Once the Memorandum of Understanding/Framework Agreement is lodged with the Government of India and accepted, suitable modification to this Scheme would be announced accordingly.

6. Use of funds provided by ECIP.

(1) All investments under the ECIP facilities in joint ventures permitted in India will be made by the partner Institutions without the requirement of any approval from the Central Government for such individual investments.

(2) The Partner Institutions shall maintain separate accounts in their books of account for the funds under the ECIP facilities handled by them on behalf of European Economic Community and for depositing the sale proceeds of its investments if any.

7. Tax Exemption

(1) The Tax exemption would be available to EEC only in respect of investments made out of ECIP funds, which would be used by the EEC through partner institutions as seed money for promoting industrial enterprises with European Investors hailing from EEC member countries in India.

(2) The Exemption from income tax on dividend, interest and capital gains tax on disinvestment available to EEC under this Scheme will not be available in respect of the equity held by foreign investors hailing from EEC member countries, or the equity held by the ECIP partner institutions out of their own funds.

[No. 15/93/89-FI&T]

P. J. NAYAK, Jt. Secy.

ANNEXURE

	Facility	Facility	Facility	Facility
	1	2	3	4
TYPE OF OPERATION	Identification of potential joint venture projects and partners.	Operations prior to launching a joint venture.	Financing of Capital Requirements.	Human Resource development : training and management assistance.
BENEFICIARIES	Chambers of commerce, Professional associations, public agencies and ECIP Financial Institutions, India. Individual companies may not benefit from facility 1.	Companies, either individual or jointly, local or European, wishing to undertake a joint venture investment project.	Joint ventures established by partners from EEC and from eligible countries. Both partners must have a meaningful participation. Investments in local companies which operate under a licensing and technical assistance agreement with an EEC Company.	
ACCESS	The beneficiary may apply directly to the EEC or through a Financial Institution.		Application to be made through a financial institution	
TYPE OF FINANCE	Grant	Interest free advance to be converted later either into a grant, a loan or equity	Equity holding or equity loan. The financial institution must cofinance the projects.	Interest free loan.
AMOUNT AVAILABLE	Maximum of 100,00 ECU	Maximum of 250,000 ECU	Maximum of 1,000,000 ECU The maximum total support per project is 1,000,000 ECU.	Maximum of 250,000 ECU
LIMITS	Upto 50% of the cost.	Upto 50% of the cost.	20% of the capital of the joint venture.	Upto 50% of the cost.

2245 G1/94-2

